

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद सूदूरप्रयाग गें राष्ट्रीय राजगार्फ-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार राहित सदक का चौड़ीकरण एंव सूष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजगार्फ एंव अपसंरचना विकास निगम लिमिटेड का यन भूमि उत्तरान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०

(यन अधिकार अधिनिगम 2008 के अन्तर्गत रामस्त यन भूमि उत्तरान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अग्रिलेख रालग्न किये जाने हैं)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli
Government Of Uttarakhand

No.....

Dated..... 21-9-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 40.8916 ha of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway & Infrastructure Development Corporation Limited "for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand."

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 40.8916hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ३.०.१...to annexure ३.०.५;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed the and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As above


मृत्ति अधिकारी
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तराय वन प्रभाग गोपेश्वर
(फौर्ली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लद्धप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District:- Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional for dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. SWATI BHADORIYA**, District Magistrate Chamoli, on dated 21-9-2019 at time ..03:00...at Chamoli in which application claiming rights in Forest Land area measuring 40.8916 ha. forest land for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place. Chamoli district
Dated 21/9/2019
SWB
प्रियांका बहादुरी

प्रियांका बहादुरी
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग नोपेश्वर
(क्षेत्री)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार राहित राड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.२

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (२.३९६९ हे० आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हे० सिविल एंव सोयम वन भूमि ६.६०० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हे० वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक २६.६.२०१९ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एंव नियम २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री द्वेषानन्द

उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमानुसार है।

- | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1. | श्री द्वेषानन्द | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी | प्रभागीय सदस्य | |
| 3. | श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव | |
| 4. | श्री वी० डी० सी० क्षेत्र | वी० डी० सी० क्षेत्र पाली | |

उपखण्ड अधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति रो बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग-०७ (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव गाननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ एंव तत्संबंधी नियम २००८ के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम २००६ के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-०७ (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहगति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(प्राधिकारी) १४५५१२ ०१०४
 नाम / प्राधिकारी नं.
 दिनांक

द्वेषानन्द नामी
 दावेदार
 कान्त पंचायत सोबला
 दिनांक १० जून २०१९ कर्णप्रयाग (बगोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एनो एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित रास्क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

Chamoli
दमधनी मेलुरी
रुद्रस्य
दोन्ह प्रायत उत्तरो
विनासा - कर्णप्रयाग चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित राझक का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हेठा आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेठा सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेठा वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 26/४/२०१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

बुशरा अंसारी

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. श्री बुशरा अंसारी | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री अमरेश कुमार | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3. श्री इ. अमरेश कुमार | संसाधन समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4. श्री जगदीश कुमार | वी० डी० सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में चमोली, राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 40.8916 हेठा वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रताव गाननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक सुपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्त्वांबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वाश अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 40.8916 हेठा वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति घोषित की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(प्राप्ति) २०१८-२ ०१२०५
प्राप्ति/प्राप्ति

नेगी
रोदिय
दात्री पंचायत सोलहा
१५०८० कर्णप्रयाग (बगोली)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव आवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन मूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीभट्ट
जनपद:- चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीभट्ट
जनपद:- चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित रास्क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.२

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिसेत्र के अन्तर्गत (२.३९६९ हेठो आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेठो रिविल एवं सोयग वन भूमि ६.६०० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेठो वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) को दिनांक ११/११/२०१० को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ एवं नियम २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| १. | श्री <u>जगदील कुमार</u> (प्रभागी) उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| २. | श्री <u>उमरुकुल</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी | उप प्रभागीय वनाधिकारी |
| ३. | श्री <u>दिलीप</u> उप सहायक समाज कल्याण अधिकारी | उप सहायक समाज कल्याण अधिकारी |
| ४. | श्री <u>दिलीप</u> वी० डी० सी० सैन्य | सदस्य / सचिव |

उपखण्ड साचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में रवागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति दो बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग-०७ (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु ४०.८९१६ हेठो वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव गाननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ एवं तत्संबंधी नियम २००८ के प्राविधिकान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम २००६ के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिसेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-०७ (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु ४०.८९१६ हेठो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सकार प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

(प्रभागी) दिनांक २०१०/११/२०१०

लेखी
राष्ट्रीय
पंचायत सोबता
१६०८० कर्णप्रयाग (घनोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली (११७)

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील:- कर्णप्रयाग / चमोली / जोशीमठ
जनपद:- चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एग० एव०-58) के कि०मी० 384.400 से कि०मी० 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नाम:- कर्णप्रयाग

वार्ड नं० -

तहसील:-कर्णप्रयाग जिला:-चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एग० एच०-58) के कि०मी० 384.400 से कि०मी० 399.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु 1.330 हेठा आरक्षित वन भूमि, 6.3995 हेठा सिविल/वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 7.7295 हेठा वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ०१५/०५/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हेठा/पत्र
नगर पालिका अधिकारी
नगर सालिकन परिषद कर्णप्रयाग
चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 384.400 से कि०मी० 399.000 में मौजूदा सड़क का चौलीकरण एंव सृद्धीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूगि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक 15/04/2019 को सम्पन्न वैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - कर्णप्रभाग

नगर पालिका का नाम:- कर्णप्रभाग

वार्ड नं० -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१-	बुद्धि की	
२-	मिठा शर्मा	
३-	मातृलाल	
४-	प्रसाद	
५-	लक्ष्मी कुमार	

३०/५८
नगर पालिका बिलासपुर
नगरपालिका बिलासपुर कर्णप्रभाग
चमोली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नालौट (तरसाली), उमरा

ग्राम पंचायत का नाम - नालौट

तहसील:- कानौप्रपण जिला:- कानौली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेतु आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेतु सिविल वन भूमि ६.६०० हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ४.१०.५.११ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में कि वन अधिकारी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लद्धप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइल का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हरतान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३.४

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - काले श्वरू

ग्राम पंचायत का नाम:- काले श्वरू

तहसील:- काले श्वरू जिला:- कामोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेठा आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेठा सिविल वन भूमि ६.६०० हेठा वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेठा वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक १०/५/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग-में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडसलाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम का नाम - कालू कालेश्वर
ग्राम पंचायत का नाम:-

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	Samnit Singh	D. S. Samnit Singh
२	Javeed Singh	Javeed Singh
३	Sandeep	Sandeep
४	Ran Lal	Ran Lal
५	अमृत सिंह	Amrit Singh



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - जयकृष्ण, झाड़

ग्राम पंचायत का नाम:- जयकृष्ण, झाड़सोली

तहसील:- कोपपुराना जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेठो आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेठो सिविल वन भूमि ६.६०० हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेठो वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ०४/०५/२०१७ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लूद्प्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० ५८०-५८) के कि०भी० ३९९.००० से कि०भी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

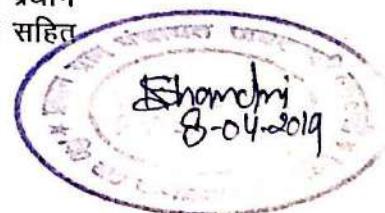
दिनांक.....०४।०५।२०१५.....को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - लंपकर्णी, रावा८

ग्राम पंचायत का नाम:- बड़खोली

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	मीरालील	मीरालील
२-	किशोरीलाल	किशोरीलाल
३-	नेम्मला कुमार	नेम्मला कुमार
४-	प्रदीप लंगा	प्रदीप लंगा
५-	सोबती हर्षी	सोबती हर्षी
६-	मामा कुमार	मामा कुमार

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊद्धरण गें राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के किमी० ३९९.००० से किमी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - उत्तरी

ग्राम पंचायत का नाम:- उत्तरी

तहसील:- ठारीप्रशाला जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के किमी० ३९९.००० से किमी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेतु आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेतु सिविल वन भूमि ६.६०० हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम दिनांक ५६/४५/२९.१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

४०/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लद्धप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के किमी० 399.000 से किमी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का बन भूगि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक....०६/०५/२०१९.....को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - उत्तरी
ग्राम पंचायत का नाम:- उत्तरी

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	रामलीला	रामलीला
२	लाला	लाला
३	मोहन सिंह	मोहन सिंह
४	महेश्वरी	Maheshwari
५	मानोज सिंह	Manoj Singh

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड वा उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - लंगास्त, निवाड़ी, उमराकोटी इफ्फ बैडागू
ग्राम पंचायत का नाम:- लंगास्त
तहसील:- कर्णपूर्णगाजिला:- चमोली-

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेठा आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेठा सिविल वन भूमि 6.600 हेठा वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेठा वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यादर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ०५/०५/२०१५ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - दुगल्वाली, विरोली, हाड़ाकोटी, नैवीतली

ग्राम पंचायत का नाम:- दुगल्वाली

तहसील:- चमोली, जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेठो आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेठो सिविल वन भूमि ६.६०० हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेठो वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ०६/०५/२०१४ को सम्पन्न वैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हेठो
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

जे.ए.पा.पा.पा.



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - झोनला, न-प्रभाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नाम:- न-प्रभाग

वार्ड नं० -

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेठो आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेठो सिविल वन भूमि 6.600 हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेठो वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ७५/५/२०१७ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष
ह०/ नगर पंचायत नन्दप्रयाग
नगर पालिका अध्यक्षद चमोली
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.०० से कि०मी० ४६०.०० में लैंडरलाइड का उपचार सहित साड़क का चौड़ीकरण एंवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

दिनांक १५/१५/२०११ को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - स्तोनला, न-कृष्णपाग, पुरसाडी
नगर पालिका का नाम:- न-कृष्णपाग,
वार्ड नं० -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	टेलाडेवी	टेलाडेवी
२	रतनालैट	Ratnay
३	आनालैट	Aanayalait
४	द्यनालैट	Dyanayalait
५	पान लिट	Palan lit
६	गबर लिट	Gabbar lit

रु०/- अध्यक्ष
नगर पालिका अध्यक्ष पदायत नुद्धप्रयाग
मुहर सहित जनपद चमाली

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - मैठाठा

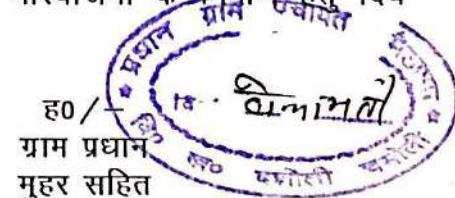
ग्राम पंचायत का नाम:- मैठाठा

तहसील:- चमोली जिला:- राजोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेतु आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेतु सिविल वन भूमि 6.600 हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ४६/०५/२०१७ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसरचना विकास निगम लिमिटेड का बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक 22/9/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - ~~कुल्हौड़ियावाल~~, गोलियाँ,

ग्राम पंचायत का नाम:- गोलियाँ

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	सुनीत शर्मा	सुनीत
२	काशित लाल	काशित
३	रविंद्र तुमरी	रविंद्र
५	मनीषिनी वरनि-लाल	मनीषिनी



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - छूमला लगा खेन्हरी

ग्राम पंचायत का नाम:- रुद्री

तहसील:- चमोली जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेठो आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेठो सिविल वन भूमि 6.600 हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेठो वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ५/३/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लूद्धप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक ०१/०३/२०१९ को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - मुमलालगा रेत्रूरी

ग्राम पंचायत का नाम:- रेत्रूरी

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	Kabir Singh	Kabir Singh
२	लाला जेट्टू	लाला जेट्टू
३	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
४	परमशाहेद दीवान सिंह	परमशाहेद दीवान सिंह
५	Balwant Singh	Balwant Singh
६	रमेश	रमेश
७	अमृतसाह	अमृतसाह
८		

हो/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लूदप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - गाड़ी
ग्राम पंचायत का नाम:- गाड़ी

तहसील:-चमोली, जिला:-चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेतु आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेतु सिविल वन भूमि 6.600 हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 25/6/2019 को सम्बन्ध बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसरण विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक २५/८/२५१ को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम का नाम - ठाड़ी
ग्राम पंचायत का नाम - ठाड़ी

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	सुरहस्ती	8/21/251 - अरबें
२	भवीष ठांडा	१२/८/251 - भवीष
३	शशीलाल	१२/८/251 - शशीलाल
४	झंडा	१२/८/251 - झंडा

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - पाखी, जलबराठ

ग्राम पंचायत का नाम:- पाखी

तहसील:- जोशीमठ जिला:- बिहोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेतु आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेतु सिविल वन भूमि 6.600 हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक ०२/०५/१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के किमी० 399.000 से किमी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक.....02/10/119.....को सम्पन्न वैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - पाखी, जलज्वाला

ग्राम पंचायत का नाम:- पाखी

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१-	रामसिंह —	रामसिंह
२-	पुष्टि रामिह —	पुष्टि रामिह
३-	भूपाललिह —	भूपाललिह
४-	देवुवीरलिह —	देवुवीरलिह
५-	सुधाइवी —	सुधाइवी
६-	बड़ी प्रसाद —	बड़ी प्रसाद
७-	खंजीतलिह —	खंजीतलिह
८-	हरिहर —	हरिहर



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - दुर्गापुरी तल्ली
ग्राम पंचायत का नाम - दुर्गापुरी तल्ली

तहसील:- जोशीमठ जिला:- उत्तराखण्ड -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेतु आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेतु सिविल वन भूमि 6.600 हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक २१/५/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

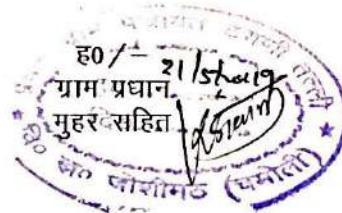
प्रारूप-३०.४

दिनांक..... २१/५/२०१९.....को सम्पन्न वैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - डंगडी तल्ली

ग्राम पंचायत का नाम:- डंगडी तल्ली

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(१)	मध्यमन लोही	लोही
(२)	रावा डोवी	डोवी
(३)	चुंकर लिंगे	लिंगे
(४)	खलाल लिंगे	लिंगे
(५)	लरोडी डोवी	डोवी



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - टंगाठी मल्ली

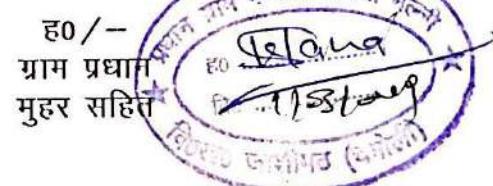
ग्राम पंचायत का नाम:- टंगाठी मल्ली

तहसील:- ऊप्रीमह जिला:- बगोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टिकरण हेतु 2.3969 हे० आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे० सिविल वन भूमि 6.600 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 40.8916 हे० वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 1/३/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



हे०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक.... ११/०१/२०१९..... को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - उंगडी मल्ली
 ग्राम पंचायत का नाम:- उंगडी मल्ली

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	द्विपदा प्रसाद	द्विपदा प्रसाद
२	सिंहराम सिंह	सिंहराम सिंह
३	राधानंद	राधानंद
४	Rohit	Rohit
५	श्रीमाम लाल	श्रीमाम लाल
६	मनोज नाथ	मनोज नाथ
७		



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नौलीवाड़
ग्राम पंचायत का नाम - गणाड़

तहसील:- जोशीमठ, जिला:- बर्मोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-58) के कि०मी० 399.000 से कि०मी० 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु 2.3969 हेठो आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हेठो सिविल वन भूमि 6.600 हेठो वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हेठो वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम दिनांक ०५/०३/२०१९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा जर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.०० से कि०मी० ४६०.०० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.४

दिनांक १५/१३/२०११ को सम्पन्न वैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - नौबीजवाड
ग्राम पंचायत का नाम:- गणाई

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१ -	कुमुडानन्द -	कुमुडानन्द
२ -	सन्दिपललम्बा -	सन्दिपललम्बा
३ -	उत्तरादेवी -	उत्तरादेवी
४ -	लोकानन्द -	लोकानन्द
५ -	महेश्वरानन्द -	महेश्वरानन्द



परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद लूदप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५०) दे कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-३०.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नगर पंचायत चौपल्कोटी, बाट्ला, जानेश्वर, संग्रामल, विरही
नगर पालिका का नाम:- पीपलकोटी, नौरख, क्षेत्रपाल
वार्ड नं० -

तहसील:- चमोली **जिला:-** चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन० एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० पर सड़क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु २.३९६९ हेतु आरक्षित वन भूमि, ३१.८९४७ हेतु सिविल वन भूमि ६.६०० हेतु वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ४०.८९१६ हेतु वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक २१.०३.१९७९ को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह० *मृ०*
नगर पालिका अध्यक्ष
मुख्यमंत्री
नगर पंचायत
चौपल्कोटी (चमोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजगार्ह-07 (पुणाना एन० एच०-५०) से किमी० ३९०.००० से किमी० ४६०.००० में लैंडस्लाइड का उपचार सहित रास्क का चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण हेतु राष्ट्रीय राजगार्ह एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का बन गृहि हरतान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक ०७/०३/२०१९ को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - बाढ़ला, गढोदा, झंगपला, नौरख, झेंपाल, विश्वी
 नगर पालिका का नाम:- पीपलकोटी
 वार्ड नं० -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	पीपल त्रिमुख	
२	पीपल आरमाल	
३	प्रभु नारायण	
४	टीपु नवाज	
५	लीला वैष्णव समाज गाँव	
६	निरामी बहसाई	
७	गोदावरी अधिकारी	
८	थमेन्द्र सिंह समाज	
९	कमलेश यादव	
१०	दिलीप लीला	
११	थमेन्द्र सिंह समाज	
१२	कमलेश यादव	
१३	दिलीप लीला	
१४	अमृता रघुवर	
१५	दीपल रघुवर	
१६	दीपल रघुवर	
१७	दीपल रघुवर	
१८	नौरज पाल यह (पांड)	
१९	पीपल राजा	
२०	मन्जुदेवी (समाज)	
२१	मन्जुदेवी (समाज)	

१०/३८
 नगर पालिका अध्यक्ष
गुरु गोप्ता
 नगर पालिका
 पीपलकोटी (बमोली)